

संपादकीय

हिमाचल में चुनाव

मतदाताओं की भी परीक्षा
श्रद्धा—1 चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा दिया है। इससे साक्षर ही राज्य में चुनाव आदर्श आचार-संहिता भी लागू हो गयी है। इस छोटें से खूबसूरत पर्वतीय राज्य में चुनावी गहमगहमी पहले से ही शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी रैली कर चुके हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया 16 अक्टूबर को अभिव्यक्त जागी होने के साथ ही शुरू होगी। 13वीं दिन से उम्मीदवार अपने नामांकन पर दाखिल कर पायेंगे। अक्सर दो दलों के बीच ही बंदी रही हिमाचल की राजनीति के लिए इस बार 9 नवंबर की तारीख निर्णायक होगी। उसी दिन राज्य के लगभग 49 लाख मतदाता 23वीं विधानसभा और भावी सरकार के लिए मतदान करेंगे, लेकिन मतदाताओं का फैसला जानने के लिए 18 दिसंबर तक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उसी दिन मतदान के बाद पांच घंटे का जनादेश किसके पक्ष में गवा। स्वाभाविक ही यह चुनाव पिछले पांच साल से सत्ता पर काबिज वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह भी माना जायेगा। भाजपा, वीरभद्र सिंह सरकार की नाकामियां गिनते हुए सत्ता का जनताक्षेत्र पाने की कवायद में कोई कमर बाकी नहीं छोड़ेगी।

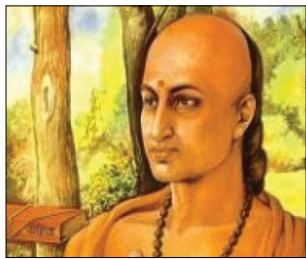
ऐसे में आने वाले दिनों में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति और भी तेज हो सकती है। वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुखचंद के बीच टकराव से त्रस्त कांग्रेस ने वीरभद्र को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर जहां तकनासिक रहत पा ली है, वहीं इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे वीरभद्र के पुत्रमोह के चलते कांग्रेस में सब कुछ सामान्य रह पायेगा, इसमें शक है। पिछले चुनावों तक भाजपा भी दो दिग्गजों—लाला कुमार और प्रेम कुमार धूमल के बीच ही बंदी रही। केंद्र में मोदी सरकार बनने तक माना जाना लगा था कि धूमन, शांता से आगे निकल गये हैं, लेकिन जेपी नूत के रूप में अब एक और सत्ता का दवेदार उभर आया है। एक ओर कांग्रेस द्वारा बुलुंग वीरभद्र को ही मुख्यमंत्री का दवेदार घोषित करने से भाजपा पर भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव बढ़ गया है, तो वैसे करने के खतरे की कमी नहीं है। जिस भी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जायेगा, उसका विरोधी गुट चुनावी भित्तबसाल में कोई करार नहीं छोड़ेगा। अगर भाजपा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया बिना ही चुनाव मतदान में उतरने का विकल्प चुनती है तो कांग्रेस को एक और चुनावी समस्या मिल जायेगी। कुल मिलाकर 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा का यह चुनाव केन्द्र दिलचस्प होने वाला है। जाहिर है, जीत तो एक की ही होगी, लेकिन सत्ता-सुधार प्रचार और प्रक्रिया सुनिश्चित करना सभी की ज़िम्मेदारी होगी।

जांच पर आंच

सुनघी नहीं आरंभ कांड की मुष्की
देश के बहुचर्चित आरंभ-हेमराज हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हम वही खड़े हैं जहां से खरें थे। कोर्ट ने भते ही परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर तत्काल दण्डित को बरी कर दिया है, मगर सवाल वही है कि फिर इस दोहरे हत्याकांड का दोषी कौन है? हालांकि, अदालत ने राजेश तलवार व दूसरे तलवार को साक्ष्यों के अनुसार में बरी किया। इस मामले में अप्रत्याश-यह नहीं है कि उन्हें निर्दोष करार दिया गया। बदरखल, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में शुमार सीबीआई की रिपोर्टताओं में एक कंडी और जुड़ गई। सवाल उठना लाजिमी है कि वे कौन से साक्ष्य थे, जिनके आधार पर गांजियाबाद की सीबीआई अदालत ने तलवार दण्डित को वही 2013 में आजीवन कारावास की सजा दी। यह भी कि वे साक्ष्य उच्च न्यायालय में क्यों नहीं टिक पाये? घटनाक्रम की परिणति हमारी पुलिस, जांच एजेंसियों, वकालत की विस्मय और मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़े करती है। जिस तरह का कोलाहल मीडिया ने इस प्रकरण को लेकर मचाया, उसने कभी न कहीं जांच प्रक्रिया पर दबाव बनाया। मामले को लेकर बित्तबे सिखी नाई, फिक्म भी बनी, मगर प्रश्न नहीं है कि इस दोहरे हत्याकांड में सीबीआई को? निश्चित रूप से अदालतें दोहरे व तर्किक सवालों के आधार पर ही न्याय करती हैं। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से फिर साबित हुआ। इस मामले में पहले S.P. पुलिस ने जिस वर-फोरेवर दया से सबूत जुटाये और हेमराज के शव की बरामगी में जिस तरह लमरबाही की, उससे कोई संदेहों को जन्म मिला? हो सकता है कि सीबीआई मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाये, मगर उसके साथ क्या खाट टिक पायेगे? सवाल यह नहीं है कि यह दिलचस्प दण्डित निर्दोष थे तो उन्हें दी गई सजा की भरपाई कैसे होगी? घटनाक्रम का एक निष्कर्ष यह भी है कि देश की पुलिस व राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के ऐसे मामलों में जांच के लिए पेशेवर दया से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

ज्ञान गंगा/ स्वामी सुखबोधानंद

जीत के लिए जरूरी है सबी नीति



जीवन में सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही आवश्यक नहीं होती बल्कि योग के द्वारा, काय व परिस्थिति के अनुसार विवाद, विरोध, जलम और मुद्द जैसी स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। महान को विपत्ति आयाय चापयोग ने सफलता के लिए कुटीनीति के चार प्रमुख अस्त्र बताए हैं, जिनका उपयोग सफल के परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यदि इन चारों को साथ लिया गया तो फिर मनुष्य की जीत सुनिश्चित है। पर यह अस्त्र हैं— साम, दाम, दंड और भेद। जब मित्रता दिखाने (साम) की आवश्यकता हो तो आवश्यक उपहार आश्रय, समरसता और संघर्ष बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। इससे दूसरे पक्ष में विश्वास पैदा होता है। यदि साम से काम न हो तो दाम यानी जलम का रास्ता अपनाया जा सकता है। यह कुटीनीति का एक अस्त्र भी दिखता हो तो दंड का इस्तेमाल उचित है। इसमें तात्काल का इस्तेमाल लाजिमी नहीं है। इसी तरह सम्य की जरूरत होने पर भेद को भी अपनाया जा सकता। इसमें दमन की सेना, मुट्ठा या धमक आधिकारिकता में फूट डालना, उसके करारी रिश्तेदारों और उच्च पदों पर स्थित लोगों से उसकी तात्काल के राज जानना आदि शामिल हैं। जीत के लिए ये अस्त्र अवश्यमय हैं।

संपादकीय

अब बदल तो रहे हैं राहुल

उपेन्द्र राय

की डमर पर चल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मुश्किलों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। राजनीति में उनके सक्रिय रहते हुए कांग्रेस ने केंद्र में सरकार तो बनाई, लेकिन उनका राहुल खल नहीं छोड़ा। उन्हें राजनीति में ‘‘बीछा और समंद देने’’, ‘‘अनुभव देने’’ और ‘‘एकन तक इंतजार करने’’ जैसी नसीहतों के साथ सरकार और पार्टी का नेतृत्व करने से दूर रखा गया। इस दौरान पीछालों की सरकार के रूप में अस्थाय ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। कांग्रेस और यूपीए में निर्णायक रहे बिना राहुल अपनी धुर विरोधी बीजेपी के हमलों के केंद्र में रहे। एक ऐसे वक्त में जब वह पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में जिताने रखने की कोशिशों में जुटे हैं,

तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी को अगर किसी नेता से डर लगता है तो वह राहुल गांधी हैं। राहुल अगर गुजरात की जंग साधने की तैयारी करते हैं, पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए प्रत्यांघा चढ़ाते हैं तो तुरंत उनके खिलाफ अमेटी में मोर्चा खुल जाता है। क्या कारण है कि राहुल अगर गुजरात से पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं तो बीजेपी अमेटी से राहुल के खिलाफ संदेश देकर इसकी भरपाई करना चाहती है?

वे मणिशंकर जैसे नेताओं को कंट्रोल में कर सके। हालांकि कांग्रेस गहलोल, कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद में दोनों पीढ़ियों के बीच संतु का काम करने का माह अब भी दिखाता है, तो अहमद पटेल अब भी पार्टी के अहम रणनीतिकार बने हुए हैं। राहुल को कभी आलाकमान की ताकत का इस्तेमाल करने का अवसर नहीं मिला। न वे कभी पार्टी अध्यक्ष रहे न सरकार में कोई मंत्री। लेकिन इसके लिए कोई और नहीं वे खुद जिम्मेदार हैं। राहुल आज जिस तरह सामने से आकर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे उन्होंने पहले कभी नहीं किया। अगर किया होता तो सवाल ही नहीं है कि यूपीए-2 में उन्हें सरकार नेतृत्व का मौका नहीं मिलता। 2014 के



आम चुनाव में भी उन्होंने खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेशा नहीं किया। ऐसे में उन्हें मनमोहन सिंह की साख पर दांव खेलता हुआ राजनीतिज्ञ माना गया। सच यह है कि माना ये गया कि मोदी के सामने राहुल को खारिज कर दिया गया है। पार्टी या सरकार का नेतृत्व नहीं करने का खतराया राहुल को इस रूप में भ्रमनात पड़ा है कि यूपीए के धकट दल ने कभी उन्हें खुलकर अपना नेता नहीं माना। अगर राहुल वे परीक्षा पास कर चुके होते तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती। आज भी ये सवाल बना हुआ कि यूपीए के धकट दल उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे या नहीं। राहुल ने लालू प्रसाद से भी एक दूरी बना ली थी, जो कांग्रेस के कमलका समर्थक और बीजेपी के धुर विरोधी रहे हैं राहुल ने कांग्रेस महासचिव और बाद में पार्टी उपाध्यक्ष के रूप में जी टीम अपने साथ बनाई वह भी वंशवाद से पैदा हुई टीम थी, कि अन्याय चमक लगाता रहा खी थी। सच ये है कि ज्योतिरिदित्य सिधिया को छोड़ दें तो जितिन प्रसाद, सविन पायलट जैसे युवा नेता भी अपने-अपने राज्यों में खुद को

प्रभावी नेता साबित नहीं कर पाए। इन नेताओं से ज्यादा यह राहुल गांधी की असफलता है क्योंकि युवा मतलों का आधार रहते हुए भी युवाओं को पार्टी से जोड़ने में नाकाम रहे। इसकी वजह शाब्द युवाओं के बीच गया यही संदेश था कि राहुल की टीम में योग्यता से ज्यादा एधुमि को तरजीह मिलेगी तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी को अगर किसी नेता से डर लगता है तो वह राहुल गांधी हैं। राहुल अगर गुजरात की जंग साधने की तैयारी करते हैं, पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए प्रत्यांघा चढ़ाते हैं तो तुरंत उनके खिलाफ अमेटी में मोर्चा खुल जाता है। क्या कारण है कि राहुल अगर गुजरात से पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं तो बीजेपी अमेटी से राहुल के खिलाफ संदेश देकर इसकी भरपाई करना चाहती है। ऐसा कर बीजेपी मोदी का बवाल भी करती है और राहुल पर हमले को और धावदार बनाती है। गुजरात में दिये राहुल गांधी के तत्पराक भाषण की सहजता हो रही है। आम जनता के साथ बितरलकों भी उनमें इलकी परिक्ता की सहजता कर रहे हैं। यूएच पर उनके भाषणों की लाइविंग बेलशा बढ रही है, लेकिन पहले राहुल अपने भाषणों में ऐसी कोई कुछ अवश्य कर जाते थे कि हकी के पात्र हो जाते थे। जिस गुजरात में राहुल का सियाह दिखे हैं(आज भी विदेश में पीएम मोदी के खिलाफ गुप्त अगर किसी को सुनते हैं तो वह राहुल गांधी ही हैं। यही कारण है कि राहुल के दो हप्ते के अमेरिका दौरे से सबसे ज्यादा पीछा बीजेपी को हो रहा है। राहुल अमेरिका में अकेले मोर्चा थामे हुए थे और उसके खिलाफ भारत में बीजेपी की पूरी टीम। बीजेपी ने चाहे सोशल

मीडिया के जरिए राहुल पर निशाना साधने में सबे को कमर नहीं छोड़ी है, लेकिन अगर वहां राहुल इतने कमजोर होते तो बीजेपी को अमेटी में राहुल के खिलाफ डेरा खेले की जरूरत ही क्यों पड़ती? यानी राहुल और कांग्रेस के लिए उम्मीद खल नहीं हुई है। पार्टी इतना बली तब तो पार्टी में लोकतंत्र की बात हो सकती। इस बात को मणिशंकर जैसे नेता नहीं समझ सकते जिन्हें जमीनी स्थिरता का कोई अनुभव नहीं है। कांग्रेस में आलाकमान संकेतों के साथ गुजरात चुनाव राहुल के लिए अतिमरहाती है। गुजरात चुनाव कोहते जाते या नहीं, मगर कांटे की टकराव देने में भी अगर वह कामयाब रही, तो पार्टी अपने लिए सोच सकती है। यह उम्मीद अभी बाकी है।

विसंगतियों की आंच

संघीय चरित्र को नष्ट करने का प्रस्ताव

तर्ह हो सकता है कि इससे चुनाव पर होने वाला भारी-भरकम चुनाव खर्च बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ चुनाव खर्च में बत करने के लिए समानांतर चुनाव का विचार देश के सामने पेश किया गया है। इरादा यह होता तो चुनाव खर्च में कमी लाने के लिए देश में हैं, जिन्हें आजगया जा सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि और खर्च की अधिकतम सीमा सिर्फ उम्मीदवारों के लिए है, मजलतिक दलों के लिए नहीं। दल वाले जितना

कने की जरूरत नहीं कि यह एकछत्र शासन को अप्रत्यक्ष निमंतणह। इससे नायक पूजा की संस्कृति और मजबूत होगी, जो हमारे यहां पहले से ही कम नहीं है। जो, समानांतर चुनाव का विरोध लोकतांत्रिक राजनीति के हक में है। शुद्ध है कि फिलहाल तो यह खामखाली ही है। पर यह बुरा समय है। आज की कौन-नी खामखाली कल यथार्थ होने के लिए व्याकुल होने लगे, कौन कह सकता है

पैसा चुनाव में झोंक सकते हैं। निश्चय ही यह लोकतंत्र विरोधी स्वतंत्रता है। राजनीतिक दलों पर भी अंधाशू लागया जा सकता है कि वे लोक सभा और विधान सभा की एक-एक सीट के लिए चुनाव प्रचार में एक सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकते। उनके खातों की ऑडिटिंग अनिवार्य कर देने से भी उनके अनाप-रानाप खर्च पर कुछ अंधाशू ला सकता है। अभी स्थिति यह है कि जिस दल के पास जितना ज्यादा पैसा है, वह

होगा कि जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है, उसके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, वह विरागति तो मित ही जाएगी। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब इसकी हलकी-फुलकी वंश शुरू भी हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। इसीलिए समानांतर चुनाव की कामना के पीछे कुछ और योजनाएँ चाहिए। इस मामले में दो

प्रसंगवश

भारतीय नारी चेतना

धारण करने की प्रतीक्षा की और कस्तूरबा ने भी कथित रूप से सहयोग किया (हालांकि स्थितियों के साथ उनके संबंध और प्रयोग को लेकर तीखी आलोचना भी हुई है, और जो आज के स्वीयादी विचारकों के अनुसंधान का धियन बन रहा है)। 1897 में गांधी जी द्वारा स्वीयादी अफीका गए और इस बार कस्तूरबा भी उनके साथ थीं अपने दो बच्चों के साथ। वही जटिल समाज-जि राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय प्रवासियों के साथ होने वाले भेदभाव के

कुल चार पुत्र हुए - हरिलाल (1888), मणिलाल (1893), रामदास (1907) और रवदास (1900)। अफीका में रहते हुए कस्तूरबा प्रवासियों के खिलाफ जुलु के विरोध में गिरफ्तार हुईं। ऐसे भी अक्सर आए जब गांधी जी, कस्तूरबा और बच्चे अलग-अलग जेलों में बंद रहे। कस्तूरबा अफीका की सरकार को अंततः सुझना पड़ा और भारतीय प्रवासियों के अधिकारों को बहाल करना पड़ा। अहिंसा और सत्याग्रह की इस जीत का श्रेय

का कभी-कभी सोचती थी कि क्या वह बापू के सच को नापने का मापक थी या माध्यम। जीवन में गतिशील और परिवर्तनकारी गांधी के साथ कदम मिला कर चलना सरल न था। सत्याग्रह, ध्या, समर्पण, त्याग और मौन के रूप में बा महानता के व्यक्तित्व में छा गई

खिलाफ अहिंसात्मक विरोध दर्ज कराने और नगरिक अधिकारों को बहाल करने की मुहिम छोड़ी। घर से बाहर निकल कर कस्तूरबा ने अपने को दूध दिया और समाजिक-राजनीतिक कार्यों के रूप में गांधी जी के साथ जुड़ गईं। 1904 में इरवन के पास फिलिप आश्रम बनाने और चलने में पति की मदद की। अफीका में भी दो बच्चे हुए। दोनों के

कस्तूरबा को भी जाता है। अगले साल इंग्लैंड होते हुए 1914 में भारत आने के बाद कस्तूरबा ने आजादी की जंग में हिस्सा लिया। वे ‘‘बा’’ बनी बह गांधी जी के साथ चंपारन की यह और यहां की ग्रामीण महिलाओं में स्वायत्त तथा पड़ोस के लिए जागरूकता फैलाई। 1922 के बंगाल के सत्याग्रह में भाग लिया। कई बार जेल गईं। 1939 में

राजकोट में अहिंसक सत्याग्रह में भाग लिया। 1942 में ‘‘अमेजो भारत छोड़ो’’ के देशव्यापी आंदोलन में गिरफ्तार भी हुईं। पुणों के आगा खास पेट्रेस में दंडित हुआ और जेल में ही उनका दहकन भी किया गया। संसद असेम में सहभागिता भी गांधी जी के बाहरी दायरे के हिस्सारे के साथ घर-परिवार और कुटुंब से जोड़ते रहते थे। बा की विशिष्ट भूमिका थी गिरिजादा किशोर आनी आध्यात्मिक रचना ‘‘बा’’ में एक प्रमुख उद्घाटन करते हैं। ‘‘कस्तूरबा से एक बार पूछा गया कि बापू के ‘‘सच के साथ बने प्रयोग’’ में आप कहां हैं? ‘‘कस्तूरबा ने कहा, ‘‘मैंने पढ़ी तो नहीं, यह ही नहीं समझी है।’’ मैं जानती हूं कि उन्होंने अमरुद होना का दायित्व दोनों के बीच बांटे हैं। मैं साजबार रखी गईं मुक्ति की बेल, उसमें मौजूद हूं। बापू ने उसमें मेरी सुंदरता का ब्यापन भी किया है, और उपयोग का भी। यह दीनता जी के न रहने का कारण मैं ही हूं। बापू ने जो सच के साथ प्रयोग किए हैं, उन्हें मैंने भीगा है।’’ बा कभी-कभी सोचती थी कि क्या वह बापू के सच को नापने का मापक थी या माध्यम। जीवन में गतिशील और परिवर्तनकारी गांधी के साथ कदम मिला कर चलना सरल न था। सत्याग्रह, ध्या, समर्पण, त्याग और मौन के रूप में बा महानता के व्यक्तित्व में छा गई। मोहनदास के महानता गांधी के साथ जुड़ने होने कस्तूरबा की सेवा, सहिष्णुता, धैर्य की भूमिका नहीं भूनाई जा सकती।

यों में थी शादीशुदा
कर भाग गए लड़के
दोनों को यहाँ पर देखा गया था।
इसलिए इस बार देखने के बाद
दोनों को पकड़ लिया गया।
प्रेमिका शादीशुदा होने के बाद भी
प्रेमी से मिलने के लिए चोरों छुपे
घर से आ जाती थी।

बाँहियों में लड़की लोके से उसके
कपड़े देने को उधरुत लगा रही थी।
पुलिस से भी कह रही थी कि पत्नियाँ
पुलिस को नहीं बुलाएँ। पुलिस से
समझने भी लड़के गंदे कमरे ट कलें
ले। बाद में सिपाही लोके को थाने
ले गए।

